को पक्का व चौड़ा किया जाना अति आवश्यक है, अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दे और उचित कार्यवाही करे।...(व्यवधान)...

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to stop the practice of writing names of great personalities in short form in English at public places

सुश्री किवता पाटीदार (मध्य प्रदेश): माननीय सभापित महोदय, मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन, सरकार और सभी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि भारत की इस पितृत धरा पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनका जीवन दर्शन हम सबके लिए आदर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप में एक पथ प्रदर्शक है। इनके नामों के द्वारा, इनके कार्यों को सिदयों तक याद रखा जा सके और इनके सिद्धांत और इनके विचार आने वाली युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करते रहें, इस भावना के साथ कई भवनों, विश्वविद्यालयों और मार्गों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर किया जाता है, परंतु आजकल एक नई परंपरा का चलन देखने को मिल रहा है, जिसे हमें निश्चित रूप से ठीक करने की आवश्यकता है। यह परम्परा नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने और पढ़ने की है। जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डी.ए.वी.वी. हो गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आर.डी.वी.वी., शहीद भीमा नायक कॉलेज एस.बी.एन. कॉलेज, रविन्द्र नाथ टैगोर मार्ग, आर.एन.टी. मार्ग, राममनोहर लोहिया अस्पताल आर.एम.एल. अस्पताल, महाराणा प्रताप नगर को एम.पी. नगर बोला जाता है। बिशम्भर दास मार्ग को बी.डी. मार्ग और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को डी.डी.यू. मार्ग बोला जाता है।

देश भर में ऐसे कई स्थान हैं, जिनके महापुरुषों के नाम से नामकरण हुए हैं, लेकिन उन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलने की परम्परा सी हो गई है। हद तो तब हो जाती है, जब टैक्सी ड्राइवर और चालक से हम किसी जगह का पूर्ण नाम लेकर पता या स्थान के बारे में पूछते हैं तो वह अनभिज्ञ रहता है, उसे पता नहीं होता है और जब हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं तो वे हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देते हैं।

'जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होगा मन' और 'जैसा पिएंगे पानी, वैसी होगी वाणी।' लगातार हमारा बोलना कहीं न कहीं प्रचलन बन जाता है। इस प्रचलन से नामकरण का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया है, नामों की प्रासंगिकता और पवित्रता ही खत्म हो गई है। यह सोचने का विषय है कि भावी पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। देश भर में ऐसे कई नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा और पढ़ा जा रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सदन, सरकार और देश की जनता से यह विनम्र अनुरोध है कि महापुरुषों के नाम को पूरा लिखा व पढ़ा जाये, ताकि उसके मूल उद्देश्य को खत्म होने से बचाया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाये गए विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गए विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गए विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गए विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गए विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SULATA DEO (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Need to restore the pre-matric scholarship for students of class 1 to 8 belonging to SC, ST, OBC and minority communities

SHRI K.R. SURESH REDDY (TELANGANA): Sir, this is an important issue -- I would like to bring it to the notice of the Government through you -- regarding the Pre-Matric scholarships which have been discontinued for the minority and OBC students. Education, as we know, is the best leveler in the society. The Delhi Declaration was way back. Primary and elementary education is the best investment India can make. As a step in that direction, for the last many decades, various steps have been taken to ensure that the weakest of the weak in the society and those children come and get educated. As a part of that issue, various measures have been taken over a period of time. With a heavy heart, I have to inform that in the midst of this academic year of 2022-23, last month, the Government issued a notice stating that the Pre-Matric scholarships for the OBCs and minorities would be discontinued. Now, we are all aware that the minorities and the OBCs are economically very weak. They need all types of support including the financial support which has been continuing. Giving them Rs.1,000 to Rs.5,000 per student under various categories per year is not really a big burden for the Government but it is a big relief for the students coming from these poor sections. It is an incentive for them to join school. It is an incentive to the families to send their children to the school and it is also an incentive to the private schools to run the schools in one of the remotest areas where Government is unable to reach. In a situation like this, without any consultation, the Government comes out and says: "The Pre-Matric scholarship will be discontinued." This has left millions and millions of students affected by this. The Government talks about "Sabka Saath Sabka Vikas Sabka Vishwas" but sabke sath, when these particular sections are eliminated from the scholarship, you would not be leaving a very good platform in the society for these people. So, I urge upon the Government to kindly reconsider it. Minorities are also a part of our society. The OBCs are also a part of our society and they are the weakest of the weak. So, it is the bounden duty of the Government. ...(Time-Bell rings.)... I have some more time as 24 seconds are left. May I continue, Sir?